

उत्तराखण्ड में चारधाम परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उत्तराखण्ड में चार प्रमुख तीर्थ स्थलों तक संपर्क सुधारने के लिये बनाई गई [चारधाम परियोजना](#) का 75% कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्य बटु

■ चारधाम परियोजना:

- इस परियोजना में [यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ](#) को बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिये **900 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क** का निर्माण शामिल है।
- यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों तक वसित है।
- नए राजमार्गों से यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी, विशेषकर **मानसून और सर्दियों के दौरान**, जब मौजूदा सड़कें भूस्खलन और अवरोधों के प्रती संवेदनशील हो जाती हैं।

■ नरीक्षण समिति:

- सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति **ए.के. सीकरी** की अध्यक्षता में एक **नरीक्षण समिति** गठित की थी।
- समिति ने परियोजना की प्रगति और दशान्तिदेशों के अनुपालन का आकलन करते हुए, अप्रैल 2024 में और **27 अगस्त, 2024 को दो रिपोर्टें** सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी हैं।

■ पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और न्यायालय के आदेश:

- संवेदनशील **हिमालयी पारसिथितिकी** तंत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इस परियोजना को वरिध का सामना करना पड़ा।
- **दिसंबर 2021** में, सर्वोच्च न्यायालय ने चारधाम राजमार्ग को **डबल-लेन चौड़ा करने** की अनुमति दी, लेकिन पर्यावरणीय क्षतिको कम करने के लिये सीकरी के नेतृत्व वाली समिति पर नगरानी की ज़िम्मेदारी सौंप दी।
- नरीक्षण समिति को नए सरे से **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह परियोजना के क्रियान्वयन की नगरानी करती है।

■ सरकारी मंत्रालयों से सहायता:

- **समिति को रक्षा, सड़क परिवहन और पर्यावरण मंत्रालयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।**
- उत्तराखण्ड सरकार और स्थानीय ज़िला मजिस्ट्रेट भी समिति के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान और **वन अनुसंधान संस्थान (देहरादून)** के प्रतिनिधि पर्यावरण नगरानी तंत्र का हिस्सा हैं।

PILGRIMS' PROGRESS

FEATURES OF REDEVELOPMENT

Realignment/ stabilization of major landslide areas, realignment away from rivers, long bridges/ viaducts & tunnel to bypass hazardous areas, reconstruction of narrow and distressed bridges, bypass for congested towns & wayside amenities

Areas for realignment and new structures have been proposed based on the ground reports of devastation during last year's heavy rain

